

बहुत दूर तक जाना पड़ता है, ये जानने के लिए, कौन करीब है।
- अज्ञात

बने रहें हमकदम

सम्मेलन के अवसर पर जारी एक संयुक्त घोषणा पत्र में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि व्यापार में तनाव और नीतिगत अनिश्चतता का वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास, व्यापार, निवेश और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अरविंद राव

ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स के ग्यारहवें शिखर सम्मेलन में दुनिया की पांच उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने संरक्षणवाद के खिलाफ कमर कसते हुए बहुपक्षीयता का झंडा बुलंद किया। उन्होंने तय किया कि इसके सामने आने वाली हर संभव चुनौती से पांचों देश मिलकर निपटेंगे। सम्मेलन के अवसर पर जारी एक संयुक्त घोषणा पत्र में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि व्यापार में तनाव और नीतिगत अनिश्चतता का वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास, व्यापार, निवेश और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में यह अहम है कि सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य एकतरफा और संरक्षणवादी कदम उठाने से बचें।

उन्होंने कहा कि हम नियमों पर आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुले, मुक्त और समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यापार

के मूलभूत महत्व को दोहराते हैं। जाहिर है, उनका निशाना अमेरिका का संरक्षणवाद है। आज जब अमेरिका तमाम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं और मानदंडों को नकार कर एकतरफा नीतियां अपना रहा है, तब इन पांच मुल्कों की आपसी समझदारी न सिर्फ इनके लिए काफी मायने रखती है, बल्कि इसका लाभ दूसरे देशों को भी मिलेगा। विश्व अर्थव्यवस्था पर अभी चौतरफा स्लोडाउन के बादल मंडरा रहे हैं। करीब एक दशक पहले भारत और चीन समेत तमाम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने जो उड़ान भरी थी, वे अभी उलटी हवाओं का सामना कर रही हैं। दुनिया को पिछली मंड़ी से बाहर निकालने वाले चीन की इकोनमी में ठहराव दिख रहा

है। साउथ अफ्रीका और ब्राजील गंभीर गतिरोध का सामना कर रहे हैं और प्रतिबंधों से घिरा रूस खुद को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटा है।

भारत की स्थिति भी इनसे अलग नहीं है और यहां मांग पर ब्रेक-सा लगा हुआ है। ऐसे में इन देशों का आपसी सहयोग एक-दूसरे को वर्तमान जड़ता से निकालने में मददगार हो सकता है। पिछले 13 सालों में इसकी छवि एक ताकतवर संगठन की बनी है, जिसकी दुनिया की कुल जनसंख्या में 42 फीसदी, वैश्विक जीडीपी में 23 फीसदी और विश्व व्यापार में करीब 17 फीसदी हिस्सेदारी है। आज यह तमाम

व्यवस्थाओं को प्रभावित करने की स्थिति में है। इसके भीतर भारत की भूमिका भी लगातार बढ़ी है। भारत की पहल पर ही ब्रिक्स ने आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त स्टैंड लिया है।

इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और नवाचार (इनोवेशन) के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कई अहम सुझाव भी दिए, जैसे अगली समिट तक 500 अरब डॉलर के आपसी व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक रोडमैप बने और पांचों देशों में उभरे एग्रीटेक स्टार्टअप अपने अनुभव साझा करें। उम्मीद करें कि आपसी सहयोग का यह सिलसिला आगे और मजबूत होता जाएगा।



विश्व अर्थव्यवस्था पर अभी चौतरफा स्लोडाउन के बादल मंडरा रहे हैं। करीब एक दशक पहले भारत और चीन समेत तमाम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने जो उड़ान भरी थी, वे अभी उलटी हवाओं का सामना कर रही हैं। दुनिया को पिछली मंड़ी से बाहर निकालने वाले चीन की इकोनमी में ठहराव दिख रहा

गतिशीलता

योगी

बचपन में मैं दोपहर के समय खेला करता था... आज की तरह कोई संरचित गेम या खेल तो नहीं था, हम बच्चों के लिए जीवन ही एक नृत्य की तरह था, शाम की हमें फिक्र भी नहीं हुआ नहीं थी। जिस पुराने मकान में हम रहते थे, उसके पीछे फल-फूलों और सब्जियों से भरा बगीचा था, हम बस उसी में तितलियां पकड़ने भागा करते थे। हमारे लिए जीवन सिर्फ वहीं तक सीमित था। जब मैं बड़ा हुआ था तो कभी-कभी ये सोचता था क्या दौड़ने का अर्थ केवल इन्द्रधनुष का पीछा करना ही है। मेरी ही तरह एक नियमित धावक, जो मेरे सीनियर थे, ने एक बार मुझे कहा कि दौड़ने का अर्थ है अपने सपने का पीछा करने के लिए फिट होना। और अगर आप किसी कारणवश गिर जाते हो तो इसका अर्थ यह भी है कि दोबारा उठो। ...दर है तो थोड़ा ठहरो और फिर से दौड़ना प्रारंभ करो।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

मौसम की उलटबांसी

इन दिनों पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अनुसार इस बार असम के 33 में से 30 जिले बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। हालांकि सरकार की तत्परता की वजह से इस बार अब तक 30 लोगों की ही मौत हुई है, जबकि 2018 में 45 लोग मारे गए थे और 2017 में 85 जानें गई थीं। बाढ़ का तात्कालिक कारण भारी वर्षा है लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि नॉर्थ-ईस्ट में मॉनसूनी बरसात में लगातार कमी आती जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम में सन 1870 से ही औसत मॉनसूनी बारिश में लगातार कमी देखी जा रही है जबकि अचानक भारी बरसात से आने वाली बाढ़ का ट्रेंड बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। औसत वर्षा में कमी आने की गति 1981 में तेज हुई। असम में औसत वार्षिक वर्षा 1,524.6 मिलीमीटर होती है। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राॅपिकल मेट्रॉलजी ने पिछले साल आईएमडी के आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। इसी अवधि में पूर्वी उत्तर प्रदेश, मेघालय, उप-हिमालयी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी औसत वर्षा में गिरावट आई, जबकि पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और दीव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पूर्वोत्तर के और राज्यों नगालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और त्रिपुरा में भी औसत वर्षा में 10 प्रतिशत की कमी आई।

यह मौसम में भारी असंतुलन का संकेत है और आगे यह और बढ़ने वाला है। इसे एक चेतावनी की तरह लेते हुए हमें अपने रहन-सहन में भारी बदलाव करना होगा, साथ ही बाढ़ और सूखे जैसी दो विपरीत आपदाओं से एक साथ निपटने की तैयारी भी रखनी होगी।

अगर देश भर में उद्योग-धंधों का समान रूप से विकास हुआ होता तो कुछ खास क्षेत्र के लोग रोजी-रोटी के लिए उद्योग-धंधों या कारोबार के मामले में समृद्ध इलाकों की ओर पलायन नहीं करते।

देश में आवाजाही

आर्दश जोशी

देश में 5.6 करोड़ लोग अपने मूल राज्य में नहीं रहते। मतलब यह कि उनका जिस राज्य में जन्म हुआ, वहां न रहकर वे किसी और राज्य में रहते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। दरअसल भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनसे बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों में शिक्षा और रोजी-रोटी के लिए जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। सेंसस के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां से सबसे ज्यादा संख्या में लोगों का पलायन दूसरे राज्यों में होता है। दूसरी ओर महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां आने वाले प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक होती है।

बिहार में बाहर से आकर बसने वालों की संख्या सबसे कम है। यहां आकर बसने वाले करीब 10 लाख प्रवासी पड़ोसी झारखंड और उत्तर प्रदेश के होते हैं। उत्तर प्रदेश में बसने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाले लोगों की है। प्रदेश में 40 लाख प्रवासी दूसरे राज्यों से आकर रह रहे हैं, जबकि प्रदेश छोड़कर जानेवालों की संख्या 1.3 करोड़ के करीब है।

दक्षिण भारत में बसे उत्तर भारतीयों की संख्या



काफी कम है। वहां बसने वाले प्रवासी ज्यादातर आसपास के राज्यों से ही हैं। यही हाल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा का है। आंतरिक आप्रवासन कहीं न कहीं विकास प्रक्रिया में असंतुलन की देन है। अगर देश भर में उद्योग-धंधों का समान रूप से विकास हुआ होता तो कुछ खास क्षेत्र के लोग रोजी-रोटी के लिए उद्योग-धंधों या कारोबार के मामले में समृद्ध इलाकों की ओर पलायन नहीं करते। हालांकि विकास की

प्रक्रिया हमेशा किसी निश्चित दिशा में नहीं चलती। एक समय उत्तर भारत के शिक्षा संस्थान देश भर में प्रसिद्ध थे और लोग उनमें दूर-दूर से पढ़ने आते थे। लेकिन पिछले दो-तीन दशकों में दक्षिण भारत शिक्षा के मामले काफ़ी आगे निकल गया खासकर विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के मामले में। इस तरह बड़ी संख्या में छात्र अब साउथ का रुख करने लगे हैं।

पलायन सिर्फ मजबूरी में ही नहीं होता। कुछ इलाकों में किसी खास विशेषज्ञता की मांग के कारण भी वहां लोग आते हैं। आज के तकनीक प्रधान दौर में माइग्रेशन एक जरूरत भी है। इसलिए इससे परेशान होने के बजाय इसे स्वाभाविक मानकर स्वीकार करना होगा। आज प्रायः हर राज्य में अनेक राज्यों के लोग रहते हैं और उसके विकास में योगदान देते हैं फिर भी कई राज्य सरकारें कई बार 'मूल निवासी' को तरजीह देने की बात करती हैं। यह एक नकारात्मक राजनीति है। एक राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को बराबर अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए चाहे वह देश के किसी भी इलाके से आकर वहां बसा हो। देश में विकास का विकेंद्रीकरण आवश्यक है ताकि कुछ खास क्षेत्रों पर जनसंख्या का बोझ न बढ़े लेकिन देश भर में लोगों की आवाजाही को नहीं रोका जा सकता।

सूंडीकू बवताल-5171				सूंडीकू बवताल-5170 का हल			
3	9		1	9	6	2	3
5	4		6	1	4	8	9
	1		7	5	7	3	6
			9	2	6	8	1
8	9		5	3	2	9	4
			3	4	1	8	7
6	1		4	9	5	4	8
			2	3	6	9	3
3	4		1	8	7	4	1
7	5		8	3	7	4	1
			6	8	3	4	1
				2	1	6	4
				6	9	5	8
				3	4	7	2
				6	5	9	1
				2	1	6	4
				7	5	9	1
				8	3	4	1
				2	3	6	4

अपना ब्लॉग

सांस लेना भी गुनाह लगता है !

बुजमोहन श्रीवास्तव। क्या हम सामूहिक आत्मघात की ओर बढ़ रहे हैं ? बिना किसी आतंकी हमले और युद्ध बम बारूद परमाणु बम विस्फोट के हम तकरीबन क्रमशः मृत्यु की ओर अग्रसर हैं और ये मृत्यु हम स्वयं चुन रहे हैं। 21 वीं सदी में पर्यावरण वैश्विक चिंता के केंद्र में आ गया है। हमारे ही देश की राजधानी दिल्ली सहित कई प्रमुख शहर प्रदूषण के कारण रहने लायक नहीं बचे हैं, ये प्रदूषण दिनोंदिन जानलेवा होता जा रहा है। इन शहरों के नागरिक नाक से सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग खांसते खांसते परेशान हैं तो दमा अस्थमा श्वास रोगियों से अस्पताल भरे जा रहे हैं। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी घातक प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली सरकार भली नीयत से गाड़ियों मोटर कार के लिए आड इवन जैसे फार्मूले आजमा रही है, स्कूल कुछ न कुछ दिन के लिए बंद किये जा रहे हैं। लेकिन जैसाकि सुप्रीमकोर्ट भी कह रहा है ये कदम काफी नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि खुद हमारी खुद की बुलाई हुई आफत है, पेट्रोल डीजल जनित धुएँ धूल-धक्कड़ का गुबार हमने पैदा किया है, जिसमें सांस लेना भी दूभर हो गया है।

फुर्सत मिले तो मासूमों की मौतों के आंकड़ों का 'योग' भी कर लें साहब!

